कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(सहकारिता प्रभाग)

सहकार संवाद

अप्रैल-जून 2023 अंक-10, वर्ष-03

निबंधक की कलम से

झारखंड राज्य के प्रत्येक पंचायत में प्राथमिक सहकारी समिति लैम्पस/पैक्स गठित हैं, जिनका निबंधन कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सहकारिता प्रभाग द्वारा किया गया है। लैम्पस/पैक्स का गठन मूलतः किसानों को कृषि में सहायता एवं सहयोग के लिये किया गया है। लैम्पस/पैक्स के सदस्य संबंधित पंचायत में निवास करने वाले किसान होते हैं। लैम्पस/पैक्स में अधिक सदस्य रहने से सभी सदस्य अपने–अपने संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर लाभान्वित होते हैं साथ–ही–साथ, समिति को हुए लाभ में से सदस्य द्वारा धारित शेयर के अनुपात में उन्हें लाभांश भी प्राप्त होता है।

माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन के निदेशानुसार राज्य के सभी किसान परिवारों को सहकारिता से जोड़ा जाना है। इसी सोच के आलोक में हूल क्रांति के महानायक अमर शहीद सिद्धो–कान्हो की जयंती के अवसर पर झारखंड राज्य के सभी लैम्पस/पैक्स में सदस्यों को जोड़ने हेतु मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन द्वारा साहेबगंज जिला अंतर्गत बरहेट प्रखंड के भोगनाडीह ग्राम में ''सदस्यता वृद्धि अभियान'' का शुभारंभ किया गया। ''सदस्यता वृद्धि अभियान'' का शुभारंभ करते हुए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भोगनाडीह लैम्पस में बने पांच नए सदस्यों को हिस्सा पूंजी के प्रमाण–पत्र का प्रतिरूप प्रदान किया गया। चिलचिलाती धूप में भी हजारों की संख्या में उपस्थित ग्रामीण किसानों के समक्ष मुख्यमंत्री ने भोगनाडीह लैम्पस के सदस्य सचिव श्री बाबूलाल सोरेन को 8,00,000 (आठ लाख) रू0 का चेक प्रतिरूप प्रदान करते हुए कहा कि लैम्पस/पैक्स किसानों की सहकारी समिति है, इसलिए सरकार द्वारा कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाती है। जिससे कि किसानों को अनुदानित दर पर बीज, खाद एवं अन्य कृषि इनपुट ससमय उपलब्ध कराया जा सके। माननीय मुख्यमंत्री का सहकारिता पर कितना विश्वास एवं लगाव है यह उस वक्त नजर आया जब सदस्यता वृद्धि अभियान समारोह में उन्होने स्वंय उपस्थित जनसमुदाय से आह्वान किया गया कि "जो किसान भाई लैम्पस/पैक्स का सदस्य नहीं बने है, वे नजदीक के लैम्पस/पैक्स में जाकर सदस्यता फॉर्म भरें और सदस्य बन जाएं। सदस्य बनना इसलिए भी जरूरी है कि सरकार किसानों को चिन्हित कर सके कि वे खेती–बारी करते है"।

हम सभी जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उत्पन्न आर्थिक एवं सामाजिक असंतुलन के परिणाम स्वरूप भारत में सहकारी आंदोलन की शुरूआत हुई, जिसके अंतर्गत लैम्पस/पैक्स, जो एक साख सहकारी समिति है, का निबंधन हुआ। यह साख सहकारी समिति एक स्वैच्छिक सहकारी संस्था है, जिसकी

सदस्यता उसके कार्यक्षेत्र में रहनेवाले 18 वर्ष या इससे अधिक के उम्र के सभी व्यक्तियों के लिए खुली रहती है।

राज्य के सभी जिलों में निबंधित लैम्पस/पैक्स की कुल संख्या 4,412 है। राज्य में 33 लाख से अधिक किसान परिवारों में से अब तक लगभग आधे परिवार ही सहकारिता से जुड़े हुए हैं। एक परिवार से एक व्यक्ति को सदस्य बनाकर शेष सभी किसान परिवारों को भी लैम्पस/पैक्स से जोड़ा जाना अत्यावश्यक है, जिससे कि वे सहकारी समिति को उपलब्ध कराए जा रही कार्यशील पूंजी, प्रज्ञा केन्द्र, गोदाम–सह–कार्यालय, कोल्ड रूम, सोलर कोल्ड रुम, रिटेल आउटलेट, कम्प्युटराईजेशन आदि का लाभ प्राप्त कर सकें। यथा–अनुदानित कृषि इनपुट प्राप्त कर कृषि उत्पाद को प्रसंस्करित, संरक्षित करते हुए विपणन द्वारा उचित मूल्यप्राप्त कर सके। लैम्पस/पैक्स द्वारा जन वितरण प्रणाली के संचालन तथा उपभोक्ता सामग्री व्यवसाय एवं सदस्यों को उनके आवश्यकता जनित उत्पाद उपलब्ध कराए जाने के साथ ही, यह सहकारी समिति Multi Purpose Unit के रूप में प्रतिष्ठित हो सकेगी।

हमारा लक्ष्य है राज्य के सभी कृषक परिवारों को लैम्पस/पैक्स के सदस्य के रुप में जोड़ा जाए जिससे किसानों की यह सहकारी समिति अपने पंचायत को सही अर्थों में एक विकसित पंचायत के रुप में सशक्त पूर्ण रुपेण सक्षम हो सके। इस कार्य में आप सभी की भागीदारी अपेक्षित है।

शुभकामनाओं सहित!

मृत्युंजय कुमार बरणवाल
निबंधक

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का 9 वाँ राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन – रायपुर

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) का 9 वाँ राष्ट्रीय स्तरीय समीक्षा सम्मेलन दिनांक 14.04.2023 से 15.04.2023 तक मे फेयर लेक रिर्सोट, अटल नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में झारखण्ड राज्य के प्रतिनिधि के रूप में निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के राज्य नोडल पदाधिकारी ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन का विषय "Take it up A Notch." था।

इस सम्मेलन में निबंधक महोदय ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की वर्तमान स्थिति झारखण्ड राज्य में इस प्रकार हैः–

1. राज्य सरकार PMFBY खरीफ 2018, रबी 2018–19, खरीफ 2019 और रबी 2019–20 सीजन के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को सभी लंबित प्रीमियम सब्सिडी प्रदान कर दी गई है तथा लंबित दावों को अविलंब निपटाने का निर्देश दिया गया है।
2. बीमा कम्पनी द्वारा संवितरित किए जाने का दावा – मो0 831.61 करोड़ रूपये जिसके विरुद्ध 692 करोड़ रूपये अब तक किसानों के दावों के भुगतान के लिए बीमा कम्पनी को प्रदान किया गया है।
3. राज्य सरकार, वित्तीय वर्ष 2023–24 में पी0एम0एफ0बी0वाई0 के लिए बजटीय प्रावधान किया है।

योजना को अगले सत्र से लागू करने के लिए राज्य सरकार को भारत सरकार से निम्नलिखित सहयोग की आवश्यकता है –

1. प्रौद्योगिकी आधारित दावा मूल्यांकन मॉड्यूल को झारखंड राज्य में लागू करने की आवश्यकता है क्योंकि सांख्यिकी विभाग द्वारा संचालित पिछली फसल कटाई आधारित पद्धति दावों के उचित अनुमान में अक्षम थी, जिसके परिणामस्वरूप दावा निपटान अनुपात बहुत ही खराब था।
2. क्षेत्रीय पदाधिकारियों के लिए हैंडहोल्डिंग और ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किए जाने की आवश्यकता है।
3. योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तर पर तकनीकी सहायता इकाई की पूर्व स्थापना।
4. राज्य सरकार के कार्यान्वयन मुद्दों के समय पर समाधान के लिए शिकायत निवारण प्रणाली।

सहकारिता

- देश के सहकारी आंदोलन में अब सहकारी समितियां की संख्या बढकर 5.03 लाख हो गयी है.
- सहकारी समिति के सदस्यों की कुल संख्या लगभग इक्कीस करोड़ है।
- देश के 100% ग्रामीण नेटवर्क तक सहकारिता की पहुँच है।
- देश के 67% ग्रामीण परिवार सहकारिता से जुड़े हुए हैं।
- कृषि ऋण का 46.31%, उर्वरक उत्पादन का 23.5%, तेल विपणन का 51%, हथकरघा का 55% और ग्राम स्तर पर 62.5% भंडारण की सुविधा सहकारिता के माध्यम से लोगों को उपलब्ध है ।

राज्य के लैम्पसों/पैक्सों को कम्प्यूटरीकृत करने की दिशा में बढ़ते कदम

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति में प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों (PACS) की दक्षता बढ़ाने तथा उनके संचालन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाने के लिये इनके कम्प्यूटरीकरण योजना को मंजूरी दी है। अगले 05 वर्षों की अवधि में देश भर में लगभग 63,000 क्रियाशील पैक्सों के कम्प्यूटरीकरण का प्रस्ताव है। केन्द्र प्रायोजित परियोजना "पैक्स का कम्प्यूटरीकरण" का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2022–23 से 2026–27 तक किया जाना है। उक्त योजना हेतु झारखण्ड राज्य अर्न्तगत कुल लैम्पस/पैक्स–4412 में से प्रथम चरण में 1500 लैम्पस/पैक्स को कम्प्यूटरीकरण हेतु सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार से स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिस हेतु सभी जिलों के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित DLIMC की बैठक कर सभी जिलों से 1500 लैम्पस/पैक्स की सूची प्राप्त हो गयी है।

योजना के क्रियान्वयन हेतु कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग), झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचना ज्ञापांक–1009 दिनांक–16.08.2022 के द्वारा SLIMC एवं DLIMC का गठन कर दिया गया है। नाबार्ड के द्वारा Software Vendor एवं System Integrators आदि के चयन के लिए Central PMU एवं State PMU का गठन कर लिया गया है। भारत सरकार के द्वारा पैक्सों के कम्प्यूटरीकरण हेतु जारी संशोधित मार्गनिर्देशिका के आलोक में उक्त योजना के निमित हार्डवेयर की खरीद की जिम्मेवारी राज्य सरकार को दी गयी है। तदनुसार राज्य सरकार के द्वारा हार्डवेयर की खरीद हेतु GeM Portal से निविदा आमंत्रित कर दी गयी है। साथ ही नाबार्ड द्वारा राज्य के लिये सुझाये गये System Integrators में से अंतिम रूप से चयन कर लिया गया है।

कम्प्यूटरीकरण के लाभ :–

- कम्प्यूटरीकरण से राष्ट्रीय स्तर पर पैक्सों में एक समान Software प्रणाली के अन्तर्गत कार्य किया जा सकेगा।
- कम्प्यूटरीकरण होने के बाद पैक्स उर्वरक, बीज आदि जैसे कृषि इनपुट के प्रावधान के लिये नोडल सेवा वितरण बिन्दु बन सकेगा।
- पैक्सों के कम्प्यूटरीकरण से बैंकिंग गतिविधियों के साथ साथ गैर–बैंकिंग गतिविधियों के केन्द्र के रूप में पैक्स की पहुँच होगी।
- कम्प्यूटरीकरण से साईबर सुरक्षा एवं आंकड़ों के संग्रहण के साथ–साथ क्लाउड आधारित साझा सॉफ्टवेयर का विकास होगा।
- पैक्स को हार्डवेयर संबंधी सहायता एवं पैक्स कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकेगा।
- कम्प्यूटरीकरण से पैक्सों को सहकारी बैंकों से जोड़ा जा सकेगा, जिससे निचले स्तर की यह सहकारी समितियॉ सहकारिता बैंक के एजेन्ट के रूप में कार्य करने लगेंगे।
- कम्प्यूटरीकरण से पैक्सों के आंकड़े को डिजिटल के रूप में संरक्षित किया जा सकेगा।
- पैक्सों के कम्प्यूटरीकरण से उनकी सहभागिता बैंकिंग, गैर–बैंकिंग, सी0एस0सी0, प्रज्ञा केन्द्र, कृषि इनपुट, PDS आदि क्षेत्रों में बढ़ेगी, जिससे उनके आय में वृद्धि होने के साथ–साथ उनके आत्मनिर्भर बनने का मार्ग प्रशस्त होगा।

सहकारी समितियों हेतु GeM पोर्टल

भारत सरकार ने सहकारी समितियों को गवर्नमेंट–ई–मार्केटप्लेस (GeM) प्लेटफॉर्म पर उत्पाद बेचने की अनुमति देने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है।

- सहकारिता मंत्रालय द्वारा GeM एसपीवी (स्पेशल पर्पज़ व्हीकल) के परामर्श से बाद स्केल अप के लिये GeM पर शामिल होने वाली सहकारी समितियों की मान्य सूची से संबंधित निर्णय लिया जाएगा।
- सहकारी समितियों को जेम पोर्टल के प्लेटफार्म पर जाने से उनके कार्यों में पारदर्शिता तो आयेगी ही साथ ही उनके उत्पाद की राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर कीमत भी मिल पायेगी

गवर्नमेंट ई–मार्केटप्लेस क्या है ?

परिचय :

- GeM विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकारों के विभागों/संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग की वस्तुओं एवं सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा के लिये वन–स्टॉप राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल है।
- GeM पर उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं के लिये मंत्रालयों व केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद करना अनिवार्य है।
- यह सरकारी उपयोगकर्त्ताओं को उनके पैसे का सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने की सुविधा के लिये ई–बोली और रिवर्स ई–नीलामी जैसे उपकरण भी प्रदान करता है।
- वर्तमान में GeM के पास 30 लाख से अधिक उत्पाद हैं, इसके पोर्टल पर अब तक 10 लाख करोड़ रुपए का लेन–देन हो चुका है।

केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना "Computerization of PACS" के सफल क्रियान्वयन हेतु मास्टर ट्रेनरों के लिए बेसिक ओरिएंटेशन प्रशिक्षण

केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना "पैक्स के कम्प्यूटरीकरण" का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2022–23 से 2026–27 तक किया जाना है। उक्त योजना के प्रथम चरण में राज्य अर्न्तगत कुल 1500 लैम्पस/पैक्स को कम्प्यूटरीकरण हेतु सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार से स्वीकृति प्रदान की गयी है।

केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना "Computerization of PACS" के सफल क्रियान्वयन हेतु सभी जिलों से चयनित मास्टर ट्रेनरों के लिए BIRD लखनऊ द्वारा एक दिवसीय बेसिक ओरिएंटेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची के सभागार में दिनांक–28.04.2023 को ऑनलाईन मोड में आयेजित किया गया, जिसमें सभी मास्टर ट्रेनरों ने भाग लिया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी प्रशिक्षणार्थियों को कुल – चार सत्रों में "पैक्सों के कम्प्यूटरीकरण" एवं उसके आलोक में मास्टर ट्रेनरों की भूमिका के संदर्भ में प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें पैक्स कम्प्यूटरीकरण (परियोजना अवलोकन) परिवर्तन प्रबंधन, कम्प्यूटर का परिचय, CoopsIndia पोर्टल, First Hand Report (FHR), Field Visit Report (FVR) की तैयारी के संदर्भ में आवश्यक जानकारी प्रदान की गयी, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:–

पैक्स कम्प्यूटरीकरण, परियोजना अवलोकन

- पैक्स का परिचय– एक SWOT विश्लेषण
- पैक्स कम्प्यूटरीकरण की आवश्यकता
- परियोजना के लक्ष्य एवं उद्देश्य
- परियोजना प्रदेय (Deliverables)
- परियोजना कार्यान्वयन तंत्र
- परियोजना लागत, फंड का स्रोत और घटक–वार व्यय का ब्रेकअप
- पैक्स के चयन के लिए मानदंड
- परियोजना निगरानी इकाईयों की संरचना, भूमिकाऐं एवं जिम्मेदारियाँ
- परियोजना के विभिन्न हितकारकों की भूमिकाऐं एवं जिम्मेदारियाँ
- कानूनी ढाँचा
- बनाई गई संपतियों का रखरखाव एवं देखभाल
- परियोजना/योजना का अपेक्षित परिणाम

परिवर्तन प्रबंधन

- पैक्स कम्प्यूटरीकरण के संबंध में परिवर्तन प्रबंधन
- पैक्स कम्पयूटरीकरण के पहले एवं बाद का तुलनात्मक व्यवसाय विश्लेषण
- विभिन्न हितकारकों के लिए कम्प्यूटरीकरण के लाभ

कम्प्यूटर का परिचय

- हार्डवेयर की खरीद
- आवश्यक हार्डवेयर
- गैर– आवश्यक हार्डवेयर
- ईआरपी
- ईआरपी की विशेषताएँ
- सिस्टम इंटीग्रेटर (SI) की भूमिका

CoopsIndia पोर्टल, First Hand Report (FHR), Field Visit Report (FVR)

- CoopsIndia पोर्टल पैक्स के लिए एक आला बहु–प्रासंगिक डेटा प्लेटफार्म
- First Hand Report (FHR) पैक्स कर्मचारियों द्वारा पोर्टल पर तैयार और प्रस्तुत (Capture) किया जाना
- Field Visit Report (FVR) उच्च वित्तपोषण एजेंसी (JSTCB/DCCB अधिकारियों) और पर्यवेक्षण अधिकारियों (सहकारिता विभाग) द्वारा समेकन एवं रिपोर्टिंग से पहले नमूनाकरण द्वारा तैयार किया जाना इत्यादि।

10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर सहकारिता सेवा के पदाधिकारियों को किया सम्मानित

चतुर्थ जे.पी.एस.सी. बैच के सहकारिता सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों की 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राँची में एक आपस मे मिलना सह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। जिसमें राज्य भर से आए चतुर्थ बैच के जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में सभी पदाधिकारी अपने परिवार तथा बच्चों के साथ उपस्थित हुए।

गिरिडीह का मधुवन पैक्स मॉडल पैक्स बनने की दिशा में अग्रसर

मधुवन पैक्स लि0, मधुवन प्रखण्ड पीरटांड़, जिला–गिरिडीह, झारखण्ड का निबंधन दिनांक 25.10.78 को हुआ। इसकी निबंधन संख्या–16/गिर 25.10.78 है।

मधुवन पैक्स लि0 द्वारा पिछले 22 वर्षो से मधुवन बाजार मेन रोड मधुवन पंचायत में संचालित है। पंचायत के 12 गांवों यथा–बगदाहा, सिंहपुर, बिरनगडडा, खपैय बेड़ा, मधुवन, जयनगर, पिपराडीह, मौजपुर, बेड़ी, बैंगनबानी, द0पारसनाथ, उ0 पारसनाथ के प्रत्येक परिवार से एक–एक व्यक्ति को सदस्य बनाया जा रहा है। वर्तमान में कुल 450 सदस्य हैं। यह पैक्स पिछले कई वर्षों से लगातार किसानों, कारीगरों, श्रमिकों एवं छोटे–छोटे दुकानदारों के लिये कार्य कर रही है। पैक्स के माध्यम से उन्नत बीज एवं उर्वरक, प्रधानमंत्री फसल बीमा, धान अधिप्राप्ति, जमा वृद्धि योजना, अल्पकालीन ऋण, अल्पकालीन उपभोक्ता ऋण, कृषि ऋण आदि प्रदान कर, कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योग का निर्माण कराते हुए उनकी सामाजिक–आर्थिक विकास कर रही है।

मधुवन पैक्स पिछले कई वर्षों से जमा वृद्धि का कार्य भी कर रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य सदस्यों में बचत की भावना विकासित करना ताकि वे आर्थिक तौर पर वे आत्मनिर्भर हो सके।

मधुवन पैक्स में कुल खातों की संख्या–2223 हैं, जिसमें, आवर्ती खाता–101, गृहलक्ष्मी खाता–61, सावधि खाता–266, दैनिक जमा खाता–236 है।

इसकी कुल कार्यशील पूंजी लगभग 25000000/– (दो करोड़ पच्चास लाख) रू0 है। कई वर्षों से पैक्स द्वारा सदस्यों एवं किसानों को कृषि एवं व्यवसाय हेतु आसानी से अल्पकालीन ऋण की सुविधा दी जा रही है। ताकि उन्हें देनदारों की चुंगल से मुक्त किया जा सके। समिति द्वारा यह ऋण की सुविधा अन्य बैंकों की अपेक्षा कम व्याज पर दिया जा रहा है। लगभग 150 सदस्यों एवं किसानों को अल्पकालीन ऋण की सुविधा प्रदान किया गया है।

मधुवन के पारसनाथ विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है। यहां सालो भर तीर्थ यात्री आते है। मधुवन बाजार में स्थानीय सदस्यों के छोटे–छोटे दुकानें हैं। इन सदस्यों को पैक्स द्वारा अल्पकालीन ऋण की सुविधा मिल रही है। जिससे उनका व्यवसाय तथा जीवन यापन चल रहा है।

इससे समिति को भी लाभ हो रही है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना धान अधिप्राप्ति वर्ष 2011 से चालू है एवं भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रज्ञा केन्द्र CSC 2021-22 से लगातार संचालित की जा रही है। जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामीणों, किसानों एवं श्रमिकों को लाभ मिल रहा है। मधुवन पैक्स को वर्ष 2019–20 में नाबार्ड प्रायोजित 80 प्रतिशत अनुदान पर आधारभूत संरचना प्राप्त हुआ। जिसका लागत मूल्य 275000/– रू0 है। पैक्स को कार्यालय में एक मॉडल सेन्टर, दो अलमीरा, गोदरेज की 15 कुर्सी, एक टेबल, एक नोट काउन्टीन मशीन CCTV कैमरा, लैपटॉप प्राप्त हुआ। जिससे पैक्स के व्यवसाय में वृद्धि हुई है तथा किसानों एवं सदस्यों को पैक्स के प्रति रूझान एवं विश्वास बढ़ा है। इसे झाम्फकोफेड एवं सिद्धो कान्हो कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लि0 की सदस्यता भी प्राप्त है।

यह पैक्स एक मॉडल पैक्स बनने की दिशा में अग्रसर है।

सोलर कोल्ड रुम से संबंधित सेमिनार

19 मई, 2023 को पशुपालन एवं सहकारिता भवन, हेसाग हटिया, रांची के सभागार में वैसे लैम्पस/पैक्स के अध्यक्ष एवं सचिवों की एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जहां पर पांच एम0टी0 क्षमता वाले सोलर कोल्ड रुम की स्थापना की गयी है।

कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए निबंधक सहयोग समितियां, झारखण्ड श्री मृत्युंजय कुमार बरनवाल ने सभी अध्यक्ष एवं सचिवों का स्वागत करते हुए उनसे आह्वान किया कि वे सभी कार्यशाला में सोलर कोल्ड रुम से संबंधित अपनी समस्याओं एवं सुझावों को खुलकर कार्यशाला में रखें तथा पूर्ण रुप से संतुष्ट होकर ही जाएं।

कार्यशाला के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए निबंधक सहयोग समितियां ने उपस्थित अध्यक्ष/सचिवों को बताया कि राज्य की भौगोलिक स्थिति तथा लैम्पस एवं पैक्स के कार्यों के आलोक में सोलर कोल्ड रुम समय की आवश्यकता है। ये तकनीकी राज्य के लैम्पस/पैक्सों के लिए नये प्रकार की है तथा संभव है समितियों को सोलर कोल्ड रुम के संचालन में पूर्व के प्रशिक्षण के बावजूद कुछ परेशानियां आ रही हों। इसी कारण सोलर कोल्ड रुम की निर्माता कंपनी के विशेषज्ञों को इस सेमिनार में बुलाया गया है ताकि वो आपको इसके और बेहतर संचालन में मार्गदर्शन दे सकें और आप उसका अधिकाधिक लाभ उठा सकें।

एक दिवसीय कार्यशाला में लैम्पस एवं पैक्स के अध्यक्ष तथा सचिवों ने खुल कर अपनी बातों एवं सुझावों को उपस्थित विशेषज्ञों के सामने रखा जिसपर सोलर कोल्ड रुम की निर्माता कंपनी के विशेषज्ञों ने उनकी बातों को गंभीरता से लेते हुए उनका मार्गदर्शन किया, उन्हे सभी आवश्यक जानकारियां दीं।

सहजन की खेती

सहजन, जिसे स्थानीय लोग "सोटी" के नाम से भी जानते हैं, झारखण्ड के किसानों के लिए एक बहुवार्षिक सब्जी देनेवाला जाना–पहचाना पौधा/पेड़ है। गाँव देहात में सहजन के लिए बिना किसी विशेष देखभाल के किसान अपने घरों के आसपास दो–एक पेड़ लगाकर रखते हैं, जिसके फल, फूल एवं पत्ती का उपयोग वे सब्जी के रूप में करते हैं।

ऐसा देखा जा रहा है कि बाजार में सहजन का फूल, छोटा–नन्हा कोमल सहजन से लेकर बड़ा और मोटा सहजन भी ऊँचे दामों में बिकता है। दक्षिण भारतीय लोग सहजन के फूल, फल, पत्ती का उपयोग अपने विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में सालों भर करते हैं भारत ही नहीं बल्कि फिलीपिंस, हवाई, मैक्सिको, श्रीलंका, मलेशिया आदि देशों में सहजन विशेष रूप से उपयोग में लाया जाता है।

सहजन के बीज से तेल भी निकाला जाता है। बीज को उबालकर सुखाने और फिर पाउडर बनाकर विदेशों में निर्यात भी किया जा रहा है। सहजन में औषधीय गुण प्रचुर मात्रा में है और इसके पौधे के सभी भागों का उपयोग विभिन्न कार्यो में किया जाता है।

सहजन भारतीय मूल का मोरिंगेसी परिवार का सदस्य है। इसका वनस्पतिक नाम मोरिंगा ओलीफेरा है। सामान्यतया यह एक बहुवर्षिक, कमजोर तना और छोटी–छोटी पत्तियों वाला लगभग दस मीटर से भी ऊंचा पौधा या पेड़ है। यह कमजोर जमीन पर भी बिना सिंचाई के सालों भर हरा–भरा और तेजी से बढने वाला पौधा है। हाल के दिनों में सहजन का साल में दो बार फलने वाला वार्षिक प्रभेद तैयार किया गया है, जो न सिर्फ उत्पादन ज्यादा देता है बल्कि यह प्रोटीन, लवण, लोहा, विटामिन–बी, और विटामिन–सी. से भरपूर है।

जलवायु: सामान्यतया 25^0–30^0 के औसत तापमान पर सहजन के पौधा का हरा–भरा व काफी फैलने वाला विकास होता है। यह ठंढ को भी सहता है। परन्तु पाला से पौधा को नुकसान होता है। फूल आते समय 40^0 से ज्यादा तापमान पर फूल झड़ने लगता है। कम या ज्यादा वर्षा से पौधे को कोई नुकसान नहीं होता है। यह विभिन्न पारिस्थितिक अवस्थाओं में उगने वाला एक ढीठ स्वभाव का पौधा है।

सभी प्रकार की मिट्टियों में सहजन की खेती की जा सकती है। यहाँ तक कि बेकार, बंजर और कम उर्वरा भूमि में भी इसकी खेती की जा सकती है, परन्तु व्यवसायिक खेती के लिए साल में दो बार फलनेवाला सहजन के प्रभेदों के लिए 6–7.5 पी.एच. मान वाली बलुई दोमट मिट्टी बेहतर पाया गया है।

सहजन का साल में दो बार फलने वाले प्रभेदों में पी.के.एम.1, पी.के.एम.2, कोयंबटूर 1 तथा कोयंबटूर 2 प्रमुख हैं। इसका पौधा 4–6 मीटर उंचा होता है तथा 90–100 दिनों में इसमें फूल आता है। जरूरत के अनुसार विभिन्न अवस्थाओं में फल की तुड़ाई करते रहते हैं। पौधे लगाने के लगभग 160–170 दिनों में फल तैयार हो जाता है। साल में एक पौधा से 65–70 सें.मी. लम्बा तथा औसतन 6.3 सेंमी. मोटा, 200–400 फल (40–50 किलोग्राम) मिलता है। यह काफी गूदेदार होता है तथा पकाने के बाद इसका 70 प्रतिशत भाग खाने योग्य होता है। इसके पौध से 4–5 वर्षो तक पेड़ी फसल लिया जा सकता है। प्रत्येक वर्ष फसल लेने के बाद पौधे को जमीन से एक मीटर छोड़कर काटना आवश्यक है।

सहजन के पौध की रोपनी में गड्ढा बनाकर किया जाता है। खेत को अच्छी तरह खरपतवार से साफ–सफाई का 2.5 • 2.5 मीटर की दूरी पर 45 x 45 x 45 सेंमी. आकार का गड्ढा बनाते हैं। गड्ढे के उपरी मिट्टी के साथ 10 किलोग्राम सड़ा हुआ गोबर का खाद मिलाकर गड्ढे को भर देते हैं। इससे खेत पौध के रोपनी हेतु तैयार हो जाता है।

सहजन में बीज और शाखा के टुकड़े दोनों से ही प्रबर्द्धन होता है। अच्छी फलन और साल में दो बार फलन के लिए बीज से प्रबर्द्धन करना अच्छा है। एक हेक्टेयर में खेती करने के लिए 500 ग्राम बीज पर्याप्त है। बीज को सीधे तैयार गड्ढों में या फिर पॉलीथीन बैग में तैयार कर गड्ढों में लगाया जा सकता है। पॉलीथीन बैग में पौध एक महीना में लगाने योग्य तैयार हो जाता है।

प्रबंधन :

एक महीने के तैयार पौध को पहले से तैयार किए गये गड्ढों में माह जुलाई–सितम्बर तक रोपनी कर दें। पौध जब लगभग 75 सेंमी. का हो जाये तो पौध के ऊपरी भाग की खोटनी कर दें, इससे बगल से शाखाओं को निकलने में आसानी होगी। रोपनी के तीन महीने के बाद 100 ग्राम यूरिया. 100 ग्राम सुपर फास्फेट. 50 ग्राम पोटाश प्रति गड्ढा की दर से डालें तथा इसके तीन महीने बाद 100 ग्राम यूरिया प्रति गड्ढा का पुनः व्यवहार करें। सहजन पर किए गए शोध से यह पाया गया कि मात्र 15 किलोग्राम गोबर की खाद प्रति गड्ढा तथा एजोसपिरिलम और पी.एस.बी. (5 किलोग्राम/हेक्टेयर) के प्रयोग से जैविक सहजन की खेती, उपज में बिना किसी ह्रास के किया जा सकता है।

सिंचाई : अच्छे उत्पादन के लिए सिंचाई करना लाभदायक है। गड्ढों में बीज से अगर प्रबर्द्धन किया गया है तो बीज के अंकुरण और अच्छी तरह से स्थापन तक नमी का बना रहना आवश्यक है। फूल लगने के समय खेत ज्यादा सूखा या ज्यादा गीला रहने पर दोनों ही अवस्था में फूल के झड़ने की समस्या होती है।

फल की तुड़ाई एवं उपज :

साल में दो बार फल देनेवाले सहजन की किस्मों की तुड़ाई सामान्यतया फरवरी–मार्च और सितम्बर–अक्टूबर में होती है। प्रत्येक पौधे से लगभग 200–400 (40–50 किलोग्राम) सहजन सालभर में प्राप्त हो जाता है। सहजन की तुड़ाई बाजार और मात्रा के अनुसार 1–2 माह तक चलता है। सहजन के फल में रेशा आने से पहले ही तुड़ाई करने से बाजार में मांग बनी रहती है और इससे लाभ भी ज्यादा मिलता है।

सहजन का गुण एवं उपयोग

सहजन बहुउपयोगी पौधा है। पौधे के सभी भागों का प्रयोग भोजन, दवा औद्योगिक कार्यो आदि में किया जाता है। सहजन में प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व व विटामिन है। एक अध्ययन के अनुसार इसमें दूध की तुलना में चार गुणा पोटाशियम तथा संतरा की तुलना में सात गुणा विटामिन सी. है।

सहजन बिना किसी विशेष देखभाल एवं शून्य लागत पर आमदनी देनी वाली फसल है। किसान भाई अपने घरों के आस–पास अनुपयोगी जमीन पर सहजन के कुछ पौधे लगाकर जहां उन्हें घर के खाने के लिए सब्जी उपलब्ध हो सकेंगी वहीं इसे बेचकर आर्थिक सम्पन्नता भी हासिल कर सकते हैं।

माननीय मंत्री श्री बादल के नेतृत्व में विभागीय टीम का केरल भ्रमण

झारखंड राज्य की जीडीपी वृद्धि में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, इसी सोच को दिशा देने के लिए राज्य के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री श्री बादल, विभाग के सचिव श्री अबुबक्कर सिद्दीख पी विभाग के अधिकारियों के साथ केरल भ्रमण पर गए। भ्रमण के दौरान श्री बादल एवं श्री अबुबक्कर सिद्दीख ने त्रिशूर के केरल कृषि विश्वविद्यालय और एग्री बिजनेस सेंटर का भ्रमण किया तथा कृषि क्षेत्र में हो रही नयी तकनीकी के प्रयोगों को देखा। केंद्र के प्रभारी ने बताया कि तकनीक के द्वारा केरल में उत्पादित विभिन्न फल सब्जियों एवं मसालों का प्रसंस्करण करते हुए वैल्यू एडिशन के साथ प्रोसेस कर प्रोडक्ट तैयार करके बाजार में उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो रही है

श्री बादल ने अपने उद्गार वक्त करते हुए कहा कि कृषि के क्षेत्र में केरल विश्वविद्यालय देश के अग्रणी विश्वविद्यालयों में है, जरुरत पड़ी तो झारखण्ड सरकार भी यहाँ की तकनीक का सहारा लेगी, यही नहीं किसानों को इसी प्रकार से प्रशिक्षण भी दिया जायेगा।

केरल के मन्नूथी स्थित कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस में माननीय मंत्री, सचिव एवं पदाधिकार्यों ने वेटनरी हॉस्पिटल के अंतर्गत पशुओं की चिकित्सा संबंधित ब्लड ट्रांसफ्यूजन, डायलेसिस केंद्र, ऑपरेशन थियेटर, और बायोकेमिकल लेबोरेटरीज, गोट फार्म आदि केंद्रों का भ्रमण किया। साथ ही उनकी कार्य पद्धति के परिचित हुए। वहां के प्राध्यापक ने मंत्री बादल को जानकारी दी कि क्लिनिक कॉम्प्लेक्स में प्रतिदिन 100 से ज्यादा विभिन्न श्रेणियों के पशुओं की चिकित्सा की जाती है। महाविद्यालय में संचालित पशु प्रक्षेत्रों के भ्रमण के दौरान वरीय प्रक्षेत्र प्रभारी ने टीम को जानकारी दी कि उनके यहां गायों की फ्रीश्वल, बछौर की नस्ल का संवर्धन के साथ साथ उनसे मॉडर्न तरीकों से दूध निकाला जाता है।

बादल ने मिल्क पार्लर का भी भ्रमण किया, साथ– साथ बकरियों की नस्ल मालबारी, जमुनापारी का कैसे संरक्षण किया जा रहा है, इसकी भी जानकारी ली। भ्रमण के दौरान कृषि मंत्री बादल ने कहा की झारखंड के पशु चिकित्सकों का एक समूह जल्द ही केरल आकर पशुपालन की आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण लेगा। इस संबंध में महाविद्यालय के डीन से प्रशिक्षण दिलाने का अनुरोध किया गया है और इसी वर्ष पशु चिकित्सकों का एक बैच केरल भेजा जाएगा। भ्रमण के उपरांत कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव श्री अबुबक्कर सिद्दीख ने कहा की केरल की पशु कल्याण और चिकित्सा पद्धति उत्कृष्ट है। उन्होंने कहा कृषि मंत्री बादल के नेतृत्व में हमने पशु कल्याण के क्षेत्र में कई काम किए हैं। हमें उम्मीद है कि केरल मॉडल पर हम जल्द काम शुरू करेंगे।

केरल के अलग अलग संस्थानों के भ्रमण के दौरान माननीय मंत्री एवं सचिव के नेतृत्व में टीम ने केंद्रीय मत्स्य प्रौद्यिगिकी संस्थान, कोच्ची का भ्रमण किया जहाँ मत्स्य से जुड़ी तकनीक एवं शैक्षणिक व्यवस्थाओं की जानकारी ली। श्री बादल ने कहा कि केरल राज्य में कृषि, पशुपालन, सहकारिता एवं मत्स्य के क्षेत्र में कई स्तर पर किये गए हैं जिसमे तकनिकी का समावेश एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारा प्रयाश होगा कि केरल राज्य की उत्कृष्ट तहत उन्नत कृषि नीति एवं तकनीक को झारखण्ड में लागू किया जाय।

नव रचना साकार हो! समाज में सहकार हो!
मंगलमय, सुखमय वैभव से, भरे–भरे भण्डार !

बिना संस्कार नहीं सहकार। बिना सहकार नहीं उद्धार ।।

झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0, राँची के निदेशक पषर्द/बोर्ड का चुनाव सम्पन्न

झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0, राँची के निदेशक पषर्द का का बहुप्रतिक्षित चुनाव (विशेष आमसभा) दिनांक 27 मार्च, 2023 को रांची के शहीद चौक स्थित मुख्यालय में संम्पन्न हुआ।

राज्य गठन के वक्त राज्य में कुल 09 केन्द्रीय सहकारी बैंक थे जिसमें से दी डाल्टनगंज केन्द्रीय सहकारी बैंक की अनुज्ञप्ति भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा रद्द कर दिये जाने के कारण वह बैंक परिसमापन में चला गया एवं राज्य में 08 केन्द्रीय सहकारी बैंक थे। धनबाद सेन्ट्रल कोओपरेटिव बैंक को छोड़कर शेष 07 बैंकों के अमेलगमेशन के उपरांत झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक का गठन किया गया है।

झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0, राँची का प्रथम निदेशक पर्षद/बोर्ड का गठनदिनांक–19.11.2018 को हुआ। झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0, राँची के निदेशक पर्षद/बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा दिनांक–07.07.2021 को त्यागपत्र, तत्कालीन मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा दिनांक–28.07.2021 को त्यागपत्र दिये जाने, चार निदेशकों के द्वारा पूर्व में भी त्यागपत्र दे दिये जाने एवं कुछ निदेशकों के द्वारा निदेशक के पद पर बने रहने हेतु अयोग्य हो जाने के फलस्वरूप झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0, राँची के निदेशक पर्षद/बोर्ड अल्पमत में आ जाने के कारण कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना संख्या–3534, दिनांक–30.07.2021 के द्वारा सरकार के स्तर से झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0, राँची में प्रशासक की नियुक्ति की गयी।

तत्पश्चात् झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0, राँची की उपविधि के नियम–20 के आलोक में निर्वाचन योग्य कुल–17 पदों के विरूद्ध निदेशक पर्षद/बोर्ड के गठनहेतु दिनांक–27.03.2023 को विशेष आमसभा–सह–चुनाव सम्पन्न हुआ, जिसमें निम्न रूप से बैंक के पदधारक निर्वाचित घोषित किये गये:–

क्र0 सं0	नाम	पदनाम
1.	श्रीमती विभा सिंह	अध्यक्ष
2.	श्री कौशलेन्द्र कुमार सिंह	निदेशक (सामान्य)
3.	श्री रमोद प्रसाद	निदेशक (सामान्य)
4.	श्रीमती अर्चना झा	निदेशक (महिला सामान्य)
5.	श्रीमती निशा रानी	निदेशक (महिला सामान्य)
6.	श्रीमती रेहाना खातुन	निदेशक (महिला सामान्य)
7.	श्रीमती सुनैना पाठक	निदेशक (महिला सामान्य)
8.	श्रीमती सोनाली कुमारी	निदेशक (महिला सामान्य)
9.	श्रीमती संगीता महली	निदेशक (महिला सामान्य)
10.	श्रीमती सरोज सिंह	निदेशक (महिला सामान्य)
11.	श्रीमती बेलीना मराण्डी	निदेशक, महिला आरक्षित (SC/ST)
12.	श्रीमती मुन्नी रजक	निदेशक, महिला आरक्षित (SC/ST)
13.	श्री चन्द्र प्रकाश	निदेशक, Professional (Under fit & proper criteria)
14.	श्री प्रभात कुमार सिंह	निदेशक, Professional (Under fit & proper criteria)
15.	श्री प्रभात कुमार अग्रवाल	निदेशक, राज्य स्तरीय समिति
16.	श्री अशोक कुमार चौधरी	निदेशक, विशेष प्रकार की समितियाँ

झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड राँची के निदेशक पर्षद के चुनाव में महिला सशक्तिकरण को स्पष्ट रूप से देखा गया। बोर्ड के कुल 16 निर्वाचित निदेशकों में से अध्यक्ष सहित 10 महिलाओं को स्थान मिला।

भारत के सहकारिता सेक्टर में एक नया revolution हो रहा है। इस बार के बजट में सहकारिता क्षेत्र को टैक्स संबंधित राहतें दी गई हैं। मैन्यूफैक्चरिंग करने वाली नई सहकारी समितियों को कम टैक्स रेट का फायदा मिलेगा।

प्रधान सम्पादक : मृत्युंजय कुमार बरणवाल, निबंधक, स0 स0, झारखण्ड **सम्पादक** : जय प्रकाश शर्मा, उप निबंधक, स0 स0
सम्पादकीय सहयोग : राकेश कुमार सिंह, स0 नि0, कुमोद कुमार, स0 नि0, कालीचरण सिंह, स0 नि0 एवं राजीव कुमार सिंह, व0 अं0 पदा0
निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची द्वारा प्रकाशित एवं अन्नपूर्णा प्रेस एण्ड प्रोसेस, राँची द्वारा मुद्रित।
पता : तृतीय तल, पशुपालन एवं सहकारिता भवन, हटिया - 834004, दूरभाष : 0651-2290444
e-mail : jharkhand.coopregistrar@gmail.com, website : cooperative.jharkhand.gov.in